mainly for exports as well as for domestic consumption.

(b) There are five meat processing units in Goa on small scale which process beef and pork together in small quantities. Such products are not exported as export of beef is banned.

(c) The total quantity of meat exported and the value thereof in the year 1991-92, 1992-93 and 1993-94 are as follows:

Year	Quantity in M.Ts.	Amount (Rs. in lakhs)
1991-92	89,081.00	22,169.00
1992-93	89,003.40	25,462.95
1993-94	110,713.00	38,700.00

The calendarwise information is not maintained. Out of the, above quantity, 6.4 MT valued at Rs. 0.95 lakhs is pork. The export of beef is banned.

(d) The assistance provided under different Plant schemes of the Ministry for developing meat and poultry sectors is as follows:

1991-92	-	Rs. 323.39 lakhs
1992-93	—	Rs. 291.35 lakhs
1993-94	-	Rs. 352.56 lakhs
1994-95 (Provisional)	—	Rs. 604.60 lakhs

The names of the recipients of the assistance are given below:

1. UP Pashydhan Udyog Nigam Ltd., Aligarh.
2. A.P. Meat & Poultry Development Corpn., Hyderabad.
3. MAFCo., Bombay.
4. Assam Livestock &, Poultry Corpn., Guwahati.
5. MP Livestock & ICukkut Vikas Nigam Bhopal.
6. Manipur State Poultry Farmers Cooperative Federation, Imphal.
7. Manipur State Piggery Farmers Cooperative Federation, Imphal.
8. Indian Veterinary Research Institute, Izzatnagar, UP.
9. Indian Institute of Packaging, Bombay.
10. Central Food Technology Research Institute, Mysore.
11. Toni Multipurpose Cooperative Society, DimapurThru' Govt. of Nagaland.
12. Mizoram Food & Allied Industries Corpn. Aizwal.
13. Karnataka Meat & Poultry Marketing Corpn., Bangalore.
14. Punjab Agro Industries Corpn., Chandigarh.
15. AP Industrial Development Corporation, Hyderabad.
16. Sukar Palak Samiti, Bhopal.
17. Poultry Cooperative Society, Aurangabad, Maharashtra.
18. Sikkim Livestock,Products Corpn., Gangtok.
19. Al Majbooh Cooperative Society Rampur.U.P.
20. Bihar Veterinary College, Patna.
21. Bombay Veterinary College, Bombay.

कम लागत वाली प्रौद्योगिकी प्राप्त करना

3874. श्री ईश दत्त यादव:
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भण्डारण प्रसंस्करण और विपणन के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी को जुटाने के प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) से (ग) सरकार देश में भण्डारण प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि के लिए कम लागत/लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहन/सहायता दे रही है। सरकार ने उद्यमियों द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने को भी उदारीकृत कर दिया है और ऐसे विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के लिए स्वत: मंजूरी की अनुमति है जिनमें कुल जानकारी, डिजाइन और ड्राइंग शुल्क आदि एक करोड़ रु से अधिक

नहीं हो। सरकार वर्कशाप, सेमीनार, विचारविमर्श और साहित्य तथा राज्य स्तर की नोडल एजेंसियों, लघु उद्योग सेवा संस्थाओं और खाद्य प्रसंस्करण परीक्षण केन्द्रों की मार्फत लागत प्रभावी/कम लागत की प्रौद्योगिकी का भी प्रसार कर रही है।

Pending applications from multinationals for investment in food processing sector

3875. MAULANAOBAIDULLAHKHAN AZMI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 5628 given in the Rajya Sabha on 4th May, 1994 and state:

(a) whether any applications from multinationals for investment in food processing industry are lying pending with the Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when these applications are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (c) While decision on the foreign investment has already been taken, action on all the other recent investment proposals by foreign companies has been initiated.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रवेश करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन

3876. श्री राम जेठमलानी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक श्रमप्रधान उद्योग है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस उद्योग में 15 लाख लोग कार्यरत हैं जो कुल श्रमशक्ति का 19 प्रतिशत हैं जबकि देश के कुल औद्योगिक पूंजी निवेश की मात्र 7.1 प्रतिशत पूंजी ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगी है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने देश की बड़ी कम्पनियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनेकों प्रोत्साहन देने की पेशकश करके इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि सरकार के इस कदम से देश में रोजगार के कम अवसर पैदा होने की संभावना के साथसाथ लघु उद्योगों के व्यापारिक हितों पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की स्थिति उत्पन्न होगी; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) जी हां।

(ख) और (ग) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1989-90 के अनुसार फैक्ट्री सेक्टर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जिनमें देश के कुल औद्योगिक पूंजी निवेश का 8.1% निवेश निहित है, में 16.02 लाख लोग कार्यरत है जो कुल जनशक्ति का 19.7% हैं। असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं।

(घ) उदारीकृत नीति के अन्तर्गत सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित उद्योग के विभिन्न सेक्टरों में बड़ी कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश का स्वागत करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उपलब्ध प्रोत्साहन सभी क्षेत्रों में लागू हैं और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर ऋण देने के अलावा 30 लाख रुपये तक उत्पादन पर उत्पाद शुल्क की छूट के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) कृषि आधारित कच्चे माल की बहुतायत मात्रा में प्रसंस्करण के लिए बड़ी क्षमताएं सृजित करने, अच्छी प्रौद्योगिकी लाने, क्वालिटी चढ़ाने, बाजार विस्तार, निर्यात बढ़ाने, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण, विपणन आदि जैसे अनुषंगी और संबद्ध क्षेत्रों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के लिए बड़ी कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों द्वारा पूंजीनिवेश की आवश्यकता होती है। खाद्य उत्पादों की कुछ मदें लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित हैं।

Downgrading the deep sea Fishing

3877. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of FOOD